RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-08
August-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i08.025

ग्रामीण विकास में मनरेगा

[1]Avinash Tiwari and [2]Dr. Ziau Rahman khan*

[1]Research Scholar, Department of Sociology, Shibli National PG College Azamgarh-276001
*[*2]Associate Professor, Department of Sociology, Shibli National PG College Azamgarh-276001*

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 17 August 2020

Keywords
आजीविका, पुनर्निर्माण, विकास, मनरेगा, प्रवास

***Corresponding Author**
Dr. Ziau Rahman khan
Associate Professor,
Email: zrkhan71@gmail.com

ABSTRACT

ग्रामीण विकास आम तौर पर अपेक्षाकृत पृथक और कम आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए 'सिल्वर क्वाइन' (चांदी की गोली) के रूप में माना जाता है, जिस तरह से गांवों में उत्पादक श्रम बल की मांग पैदा करते हैं। यह आजीविका का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है, जो प्रवासन को कम करने, बाल श्रम को रोकने, गरीबी को कम करने, और सड़क निर्माण, पानी के टैंक की सफाई, मिट्टी और जल संरक्षण आदि कार्य जैसे उत्पादक संपत्ति निर्माण के माध्यम से गांवों को आत्मनिर्भर बनाने पर प्रभाव डालेगा। जिसके लिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा गरीबी-विरोधी कार्यक्रम माना गया है। इस शोध पत्र में, द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर, विभिन्न माध्यमिक आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण जीवन और आजीविका के पुनर्निर्माण के लिए विकास के प्रयासों को व्यापक रूप से समझने का प्रयास किया गया है।

परिचय

"भारत में, 121 करोड़ की कुल जनसंख्या में से, 83.3 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं"[1]। इस प्रकार, भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इन ग्रामीण आबादी को बड़े पैमाने पर गरीबी, साक्षरता के निम्न स्तर और आय, बेरोजगारी के उच्च स्तर और खराब पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति की विशेषता हो सकती है। इन विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए, इन ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के अवसर पैदा करने के लिए कई ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास शब्द ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास है। और "यह ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में विशेष रूप से गरीबों के स्थायी सुधार के लिए एक प्रक्रिया है।"[2] ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी और बेरोजगारी को कम करने, स्वास्थ्य और शैक्षिक स्थिति में सुधार लाने और ग्रामीण आबादी के भोजन, आश्रय और कपड़ों जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का इरादा रखते हैं। ग्रामीण लोगों की स्थितियों में सुधार करने के लिए, "भारत सरकार ने भारत के योजना आयोग के माध्यम से कुछ योजनाएं शुरू कीं जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), राष्ट्रीय विकास योजना (RSVY), प्रधानमंत्री (PMAY), एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (ITDP), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS), ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (DWCRA), आदि"[3]। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच अंतर को कम करना है जो असंतुलन को कम करने और विकास प्रक्रिया को गति देने में मदद करेगा।

मनरेगा: ऐतिहासिक परिपेक्ष्य

स्वतंत्रता के बाद की अवधि में, सरकार अपने लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान करना चाहती थी जो मुख्य रूप से दैनिक श्रम पर निर्भर थे। सरकारी परिप्रेक्ष्य का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक ग्रामीण आबादी को कृषि आबादी के रूप में बसाना था। "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 किसी वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के लिए तैयार हों। यह अधिनियम शुरुआत में 200 जिलों में फरवरी, 2006 से प्रभावी हो गया था और बाद में इसे वित्तीय वर्ष 2008-09 से भारत के सभी ग्रामीण जिलों तक बढ़ा दिया गया था। मनरेगा अन्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लगभग 56 वर्षों के अनुभव के बाद आया है, जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाएं और राज्य सरकारों द्वारा लॉन्च किए गए दोनों शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) 1980-89; ग्रामीण भूमिहीन

रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) 1983-89; जवाहर रोजगार योजना (JRY) 1989-1990; रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) 1993-99, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY) 1999-2002; सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना (SGRY) 2001; नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम (NFFWP) 2004 शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में, SGRY और NFFWP 2005 में नरेगा में विलय कर दिया गया है। अधिनियम चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया था - 2007-08 में 130 जिले जोड़े गए थे। देश भर में 625 से अधिक जिलों में फैलने के साथ, ग्रामीण गरीबों की क्रय शक्ति बढ़ाने, प्रवास संकट को कम करने पर बल दिया गया। साथ ही, यह सामाजिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा दे सकता है क्योंकि योजना के तहत 23 प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जाति, 17 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और 50 प्रतिशत महिलाएँ हैं। 2016-17 में, लगभग 70 मिलियन घरों को नरेगा के कामों में लगाया गया था। यह अधिनियम ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध या अकुशल कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या न हों"[4]।

वर्तमान अध्ययन

वर्तमान शोध पत्र में, हमने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की समीक्षा माध्यमिक डेटा की सहायता से विस्तार से की है। डेटा ग्रामीण विकास अनुभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग आज़मगढ़ जिला प्रशासन से एकत्र किया गया था। प्रथम केस फील्ड कार्य के आधार पर दो केस स्टडी का भी हवाला दिया जाता है। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य समग्र परिदृश्य का आकलन करना है, अर्थात, इस योजना के साथ जुड़े हुए पक्ष और विपक्ष निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ हैं:

1. मनरेगा के विकास के साथ-साथ ग्रामीण लोगों के जीवन पर विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के समग्र सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन और अधिग्रहण करना।
2. घरेलू स्तर और ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण गरीबों के जीवन में मनरेगा द्वारा लाए गए सुधार या परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण करना।

मनरेगा: वर्तमान स्थिति

कई लेखकों ने मनरेगा के बारे में विस्तार से और इसके संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने का प्रयास किया है। ड्रेसेज़ (2007)[5] उड़ीसा (भारत) में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार को देखते है और यह कैसे एक नरेगा में भी जारी रहा है। माथुर (2007)[6] के अनुसार, व्यक्तियों और समूहों की पहल पर निर्भर ऐच्छिक रिपोर्टों और अध्ययनों के विपरीत, आधिकारिक जानकारी के नियमित और निरंतर प्रवाह की एक प्रणाली आवश्यक है। कार्यान्वयन में सुधार के लिए, सरकार को समस्याओं को हल करने, नीति निर्देशों को संशोधित करने और जिला, ब्लॉक और गांव के स्तरों के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी करने की आवश्यकता है। सरकार को नेतृत्व करना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, संस्थानों और समूहों को संगठित करना चाहिए। मनरेगा में विभिन्न स्तरों पर कई लाख सरकारी अधिकारी, पंचायत अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन और सामुदायिक समूह शामिल हैं। वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन चुनौती के लिए बहुत कम तैयारी के साथ । नरेगा वास्तव में राष्ट्रीय महत्व का एक कार्यक्रम है जिसे हाशिए पर रखा गया है जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र में नोडल मंत्रालय है, हर संबंधित विभाग और एजेंसी को शामिल करने की आवश्यकता होती है।

Ambasta et al. (2008)[7] ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दीं। इनमें सभी स्तरों पर विशेष रूप से ब्लॉक स्तर पर मनरेगा के लिए समर्पित पूर्णकालिक पेशेवरों की तैनाती शामिल थी। क्षमता निर्माण, आकर्षक सरकारी और गैर-सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर पूरी तरह से प्रशिक्षित जमीनी कार्यकर्ताओं के विशाल कैडर के निर्माण में गहन प्रयास की आवश्यकता है।

मेहरोत्रा (2008)[8] एक सिविल सेवक जिसने योजना के कार्यान्वयन में काम किया है, का मानना है कि प्रशासनिक लागत और पेशेवर समर्थन के रूप में आवंटित कार्यक्रम की लागत का 4 प्रतिशत अभी भी काफी कम है और इस तथ्य को मान्यता नहीं देता है कि मनरेगा के पैमाने पर एक कार्यक्रम गंभीर पेशेवर समर्थन की आवश्यकता है।

खेरा (2008)[9] का मानना है कि उड़ीसा (भारत) राज्य में पाटी ब्लॉक में मनरेगा का सफल कार्यान्वयन अपने निवासियों के अधिकारों का दावा करने की क्षमता से परे है। यह योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के मामले में कार्यक्रम के साथ व्यतता के उच्च स्तरों द्वारा लाया जाता है।

माथुर (2009)[10] का कहना है कि आंध्र प्रदेश (भारत) में किए गए सोशल ऑडिट में यह पाया गया कि कुछ गांवों में, कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें किए गए काम के लिए भुगतान नहीं किया गया था। जब जॉब कार्ड के अनुसार भुगतान के साथ पास-बुक के अनुसार भुगतान की तुलना की गई थी, तो यह पता चला कि जॉब कार्ड में आंतरिक पृष्ठ नहीं थे जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए काम को रिकॉर्ड करते हैं; जॉब कार्ड खुद अधूरा था।

मनरेगा को सख्त गरीबों के लिए एक सहायता प्रणाली की जरूरत है और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सक्षम, प्रोत्साहित और सशक्त बनाना चाहिए। "अपने वर्तमान प्रारूप में, मनरेगा एक और सब्सिडी कार्यक्रम बन सकता है जो राष्ट्र पर बोझ बनने का जोखिम चलाता है"।[11]

ग्रामीण विकास समय की जरूरत है। यह न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का गठन करता है, बल्कि इसका उद्देश्य सामूहिक प्रक्रिया के माध्यम से ग्रामीण गरीबों की भलाई और जीवन स्तर में सुधार करना है। समीक्षा से यह स्पष्ट है कि-यह कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों में लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए है, लेकिन यह कार्यक्रम कई कमियों से ग्रस्त है। इस प्रकार, साहित्य की विस्तृत समीक्षा स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि ग्रामीण भारतीय पर मनरेगा कार्यक्रम के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को समझने के लिए व्यापक मानवविज्ञान अनुसंधान कार्य की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय अवलोकन

निम्नलिखित मामले के अध्ययनों का उल्लेख भारत के आज़मगढ़ में जिले के ग्रामीण इलाकों से आयोजित प्रथम-क्षेत्रीय कार्य के आधार पर किया जाता है।

मामला एक:- नाम-जयलक्ष्मी आयु: 45 आज़मगढ़ के रानी की सराय पंचायत में रहती हैं। वह एक विधवा है और उसका एक बेटा है जो बारहवीं कक्षा में पढ़ता है। वह कहती हैं कि कृषि कार्य एक वर्ष में केवल 6 महीने के लिए उपलब्ध होता है और वह भी निरंतर नहीं। धान की कटाई जैसे कुछ काम करते हैं। हालांकि वह मनरेगा के तहत काम करने में सक्षम है। उसने 2017-2018 में 30 दिनों के लिए काम किया है और उसने अपने बेटे की शिक्षा का समर्थन करने के लिए अर्जित आय का उपयोग किया है। वह खुश है कि मनरेगा मजदूरी का भुगतान हर हफ्ते किया जाता है और वह अपने बेटे के लिए एक कार्ड प्राप्त करना चाहती है ताकि वह भी काम कर सके।

केस 2: नाम-मोगरा उम्र: 34 वह रानी की सराय पंचायत के गाँव में रहती है। उसके पास बीपीएल कार्ड है और उसका परिवार एक कच्चा घर में रहा करता था। हाल ही में उन्होंने और उनके पति ने उनके लिए एक ईंट घर बनाया। उसे गाँव में एक सार्वजनिक घोषणा के माध्यम से मनरेगा के तहत प्रावधानों के बारे में पता चला। उसने मनरेगा के तहत काम करने का फैसला किया। पिछले साल उसने और उसके पति ने 100 दिनों तक मनरेगा के तहत काम किया और औसत मज़दूरी की दर से अच्छी कमाई की। छोटी मात्रा की भूमि जो उनकी बुनियादी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अंत में, उन्होंने मनरेगा द्वारा उनके लिए पक्का घर बनाने के लिए अर्जित धन को खर्च करने का फैसला किया।

इस प्रकार, उपर्युक्त मामलों से यह स्पष्ट है कि भारत में मनरेगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम है क्योंकि यह ग्रामीण गरीबों को अपनी आजीविका कमाने में मदद करता है। यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक लंबा रास्ता तय कर सकता है।

निष्कर्ष

लगभग 70 प्रतिशत भारतीय आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता वैसी ही होनी चाहिए जैसी उप-नगरीय और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होती है। इसके अलावा, शहरी केंद्रों पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, गरीब और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के व्यापक प्रभाव सामाजिक अभाव और शहरी गरीबी में प्रकट होने वाले सामाजिक-आर्थिक तनावों के लिए अग्रणी है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को भारतीय गांवों में उत्पादक श्रम बल की मांग पैदा करने के माध्यम से ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए "सिल्वर बुलेट" के रूप में माना जाता है। यह आजीविका का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है, जो प्रवासन को कम करने, बाल श्रम को रोकने, गरीबी को कम करने, और सड़क निर्माण, पानी के टैंक की सफाई, मिट्टी और जल संरक्षण कार्य आदि जैसे उत्पादक संपत्ति निर्माण के माध्यम से गांवों को आत्मनिर्भर बनाने पर प्रभाव डालेगा, जिसके लिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा गरीबी-विरोधी कार्यक्रम माना जाता है।

चूँकि यह योजना असीमित अवधि के लिए लागू है, और गुंजाइश एवं भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में बढ़ रही है, इसके प्रभाव में गैर-समरूपता, क्षेत्र विशिष्ट विषमता और परिणाम आदि जैसी कई चुनौतियाँ हैं। इस वजह से कुछ एनजीओ पहले ही कुछ सर्वे कर चुके हैं। हालांकि, वे लाभार्थियों पर अपने कार्यक्रमों के प्रभाव की जांच करने के बजाय, एक या दो जिलों तक ही सीमित हैं।

दो अलग-अलग रणनीतियों के साथ इन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की गहन समीक्षा करने की आवश्यकता है, (i) देश के सभी कोनों से संकेतों को कैप्चर करके, सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय अध्ययन और (ii) व्यापक रूप से मनरेगा में संरक्षित सभी उद्देश्यों और खंडों की व्यापक कवरेज। इस प्रकार, इस कार्यक्रम की क्रियान्वयन प्रक्रिया और ग्रामीण लोगों की आजीविका पर इसके प्रभाव की गंभीर रूप से जांच करने की आवश्यकता है। यह निष्कर्ष

निकाला जा सकता है कि इस अधिनियम की सफलता इसके उचित क्रियान्वयन पर निर्भर करती है और इस परिदृश्य में, इस कार्यक्रम को बहुत प्रभावी बनाने के लिए समुदाय की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है।

संदर्भ सूची

[1]. http://www.hi.m.wikipedia.org/wiki/ भारत की जनसँख्या

[2]. http://www.hi.vikashpedia-in/social.welfare

[3]. http://www.india.gov.in/hi/ ग्रामीण-विकास-योजनाएं

[4]. http://www.nrega.net , http://www.nrega.nic.in/guidelines.htm.

[5]. Dreze J. (2007). MGNREGA: Dismantling the contractor raj. *The Hindu*, 20th November, 2007.

[6]. Mathur L. (2007). Employment guarantee: Progress so far. *Economic and Political Weekly*, December 2007.

[7]. Ambasta, P., Shankar, P.S.V., & Shah, M. (2008). Two years of MGNREGA: The road ahead. *Economic and Political Weekly*, February 2008.

[8]. Mehrotra, S. (2008). NREG two years on: Where do we go from here? *Economic and Political Weekly*, August 2008.

[9]. Khera, R. (2008). Empowerment Guarantee Act. *Economic and Political Weekly*, August 2008.

[10]. Mathur, L. (2009). Silent but successful initiative. *The Hindu*, 1st March, 2009.

[11]. The Economic Times, 2009